

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्ली: श्रावण 13, 1944

बृहस्पतिवार: 04 अगस्त 2022

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरल भूमि प्रबंधन की आवश्यकता: रक्षा मंत्री भूमि उपयोग सॉफ्टवेयर पर डीजीडीई वेबिनार के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों को संबोधित करते हुए

"डीजीडीई द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर रक्षा भूमि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करेगा"

श्री राजनाथ सिंह ने डीजीडीई को दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों से भारत के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भूमि का सरल प्रबंधन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री 04 अगस्त 2022 को केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों के व्यापक उपयोग और अनुकूलन क्षमता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव (सीओई-सुरवेई) द्वारा विकसित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित अनुप्रयोगों का प्रसार करने के लिए आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

सीओई-सुरवेई की स्थापना रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि सर्वेक्षणों में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग, डेटा और भूमि प्रबंधन के विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पिछले कुछ महीनों में, केंद्र ने प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम; भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर; राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र; आईआईटी दिल्ली और अन्य केंद्र सरकार के संगठन के सहयोग से कई सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा, "निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करते हुए, सीओई-सुरवेई हमारे देश की भूमि सर्वेक्षण, विश्लेषण और प्रबंधन से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीओई-सुरवेई द्वारा विकसित अनुप्रयोगों में परिवर्तन का पता लगाने, भूमि उपयोग विश्लेषण और 3डी इमेजरी विश्लेषण अनुप्रयोगों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर रक्षा भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की जानकारी देता है। अनुप्रयोग, जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है, सभी 62 छावनी बोर्डों में स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भूमि पर स्थायी प्रकृति के परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं, जिससे वे यह जांच सकते हैं कि क्या ऐसे परिवर्तन अधिकृत हैं या सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना हैं। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण के विरुद्ध समय पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने में मदद करता है। इससे पहले, इस तरह के अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों की जानकारी भौतिक सत्यापन के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। श्री राजनाथ सिंह ने इस सॉफ्टवेयर को प्रभावी और समय की बचत वाला बताया जो भूमि स्वामित्व और भूमि का उपयोग करने वाले विभागों द्वारा निगरानी बढ़ाने में मदद करेगा और अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को प्रतिबंधित करेगा।

नैसैंट इन्फोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित भूमि उपयोग विश्लेषण सॉफ्टवेयर, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग (आरएस) प्रौद्योगिकियों के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी स्थान का विश्लेषण कर सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपकरण न केवल रक्षा मंत्रालय के लिए बल्कि अन्य सरकारी और राज्य विभागों के लिए भी सहायक साबित होगा, जो मौजूदा भूमि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के 3डी इमेजरी विश्लेषण और दृष्टिगत चित्रण के लिए उपकरण विकसित करने हेतु सीओई-सुरवेई के प्रयासों की भी सराहना की।

यह इंगित करते हुए कि विश्व की जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है, रक्षा मंत्री ने इसके अनुकूलतम उपयोग के लिए भूमि जैसे अद्वितीय संसाधनों के प्रभावी और विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी हितधारकों से भूमि के सर्वेक्षण और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।

अपने संबोधन में, श्री राजनाथ सिंह ने भूमि विवाद जैसे विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'भूमि विवाद जैसे मुद्दे विकास प्रक्रिया में बाधा बन जाते हैं। हमारी सरकार ने भूमि से संबंधित कई अप्रासंगिक पुरातन कानूनों को निरस्त कर दिया है। आज भारत उन देशों में से एक है, जहां गांवों में भी ड्रोन की मदद से भूमि रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी-एमआईएस 2.0) के अनुसार, लगभग 94% गांवों के भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया गया है। इसके साथ, लोग अपनी भूमि का एक स्पष्ट शीर्षक प्राप्त करने में सक्षम हैं।"

स्पष्ट भूमि शीर्षकों के महत्व को रेखांकित करते हुए, रक्षा मंत्री ने उन्हें न केवल निवासियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताया, बल्कि नए सेट-अप स्थापित करने में उद्योगों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यदि भारत विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, व्यवसायों और निवेश को आकर्षित करना चाहता है या समान क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनना चाहता है तो इसके लिए स्पष्ट भूमि शीर्षक एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

श्री राजनाथ सिंह ने छावनी बोर्डों के विकास और इसके निवासियों के जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए डीजीडीई के ऐसे अन्य प्रयासों की सराहना की। इनमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का सर्वेक्षण और सीओई-सुरवेई की स्थापना के अलावा 'ई-छावनी' पोर्टल की शुरुआत शामिल है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के समर्थन से डीजीडीई को ऐसे और सुधारों के साथ आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से डीजीडीई के कामकाज में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

डीजीडीई द्वारा अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के साथ एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य दैनिक कार्यों में ऐसे उपकरणों को अपनाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और उनकी आगे की अनुकूलन क्षमता और उन्नयन के लिए विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्राप्त करना है।

इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, रक्षा संपदा महानिदेशक श्री अजय कुमार शर्मा, रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी; विभिन्न केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारी और छावनी बोर्डों के फील्ड अधिकारी और डीईओ उपस्थित थे। वेबिनार के दौरान, विशेषज्ञ एजेंसियां/विभाग जीआईएस और आरएस उपकरणों पर प्रस्तुतियां देंगी जो या तो विकास के अधीन हैं या पहले से ही विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में हैं।

एबीबी/डीके/डीएस